



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49 ]  
No. 49]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 1997/फाल्गुन 26, 1918  
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 1997/PHALGUNA 26, 1918

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1997

गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिकारिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा अपनायी जाने वाली निवेश की पद्धति

सं० एफ० 11( 2 )-पी० डी०/96.—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 11( 1 ) पी०डी०/95, दिनांक 26 मई, 1995 और संख्या 11( 2 )-पी० डी०/96, दिनांक 16 सितम्बर, 1996 का अधिक्रमण करते हुए गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिकारिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा शृद्धिशील संग्रहणों हेतु निवेश की पद्धति 1 अप्रैल, 1997 से निमानुसार संशोधित रूप में प्रभावी होगी :

निवेश की पद्धति

निवेश की जाने वाली राशि की प्रतिशतता

(i) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	पच्चीस प्रतिशत
(ii) (क) किसी भी राज्य सरकार द्वारा स्थापित और निर्गमित सरकारी प्रतिभूतियां जो कि लोक आण अधिनियम, 1944 (1944 की 18) को धारा 2 में परिभाषित की गई हैं और वा	}
(ख) कोई अन्य प्रक्रम्य प्रतिभूतियां, जो नीचे (3)(क) के अन्तर्गत आई हैं उन्हें छोड़कर, जिनके मूलधन और उन पर व्याज की पूरी और बिना शर्त गारंटी केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार ने दी हो।	

(iii) (क) कंपनी अधिनियम की धारा 4(क) के अन्तर्गत यथा-विनिर्दिष्ट “सार्वजनिक विस्तीर्ण संस्थाओं”, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(36-क) में यथा परिभाषित “सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों” के बांड/प्रतिभूतियां: और या (ख) सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा जारी जमा राशियों के प्रमाणपत्र (iv) चालिस वर्षों द्वारा यथा-निर्धारित उपरोक्त तीन श्रेणियों में से किसी में निवेश किया जाएगा। } चालीस प्रतिशत } बीस प्रतिशत } } 2. कोई भी धनराशियां जो पूर्ण में किए गए निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त होती हैं, वहाँ ऐसी धनराशियों में से आवश्यक व्यय को घटाकर उन्हें अधिसूचना में निर्दिष्ट निवेश पद्धति के अनुसार निवेशित किया जाएगा। 3. विशेष जमा योजना से मिलने वाले व्याज को इसी विशेष जमायोजना में निवेशित किया जाएगा। इसी तरह अन्य श्रेणियों के अन्तर्गत प्राप्त व्याज को उसी श्रेणी में पुनः निवेशित किया जा सकता है। 4. उपर्युक्त पैराग्राफों में यथा परिकल्पित निवेश पद्धति वित्तीय वर्ष के अन्त सक लागू की जा सकती है।

एम० आर० सौधरी, निदेशक (बजट)

**MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 1997

**Pattern of investment to be followed by the Non-Government Provident Funds, Superannuation Funds and Gratuity Funds.**

No. F. 11(2)—PD/96.—In supersession of this Ministry's Notifications No. 11(1)—PD/95 dated 26th May, 1995 and No. 11(2)—PD/96 dated 16th September, 1996, the pattern of investment for incremental accretions by the Non-Government Provident Funds, Superannuation Funds and Gratuity Funds shall stand revised as follows effective from 1st April, 1997 :—

**INVESTMENT PATTERN**

	Percentage amount be invested
(i) Central Government Securities	Twenty Five Percent
(ii) (a)Government Securities as defined in Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government; and/or	}
(b)Any other negotiable securities the principal whereof and interest whereon is fully and unconditional guaranteed by the Central Government or any state Government except those covered under iii (a) below.	}
(iii) (a)Bonds/Securities of 'Public financial institutions' as specified under section 4 (a) of Companies Act: "Public Sector Companies" as defined in Section 2(36-A) of the Income Tax Act, 1961 including public sector banks; and/or	}
(b) Certificate of deposits issued by public sector banks.	Fifteen percent
(iv) To be invested in any of the above three categories as decided by the Trustees.	Forty percent
	Twenty percent

2 Any moneys received on the maturity of earlier investments reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the investment pattern prescribed in this Notification.

3 Interest received on the Special Deposit Scheme shall be invested in the Special Deposit Scheme itself. Similarly, interest received under other categories may be re-invested in the same category.

4. The investment pattern as envisaged in the above paragraphs may be achieved by the end of a financial year.

M. R. Choudhary, Director (Budget)